HRA an USIUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--ठप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

tion (i)

संं⁰ 164] No. 164] नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 1998/वैशाख 23, 1920 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 1998/VAISAKHA 23, 1920

लोक सभा सचिवालय

अविस्चना

नई दिल्ली, 6 मई, 1998

सा. का. िम. 247(अ).—दिनांक 19 दिसम्बर, 1957 के भर्ती तथा सेवा शर्ते आदेश सं. 185 द्वारा लोक सभा सिववालय के अधिकारियों पर लागू किए गए मूल नियमों के नियम 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सभा के अध्यक्ष लोक सभा सिववालय (आवासों का आबंटन) नियम 1974 में और संशोधन करने हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों को लोक सभा समिवालय (आवासों का आबंटन) संशोधन नियम, 1998 कहा जाएगा।
- (2) इन नियमों को 1 जनवरी, 1997 से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा।
- 2. लोक सभा सचिवालय (आवासों का आबंटन) नियम, 1974 में,

नियम 8 में, उप-नियम 2 के नीचे दी गई तालिका में सेवा निवृष्ति या सेवान्त अवकाश से संबंधित मद (दो) के समक्ष आवास प्रतिधारण की अनुज्ञेय अविध से संबंधित कालम के अंतर्गत ''दो माह सामान्य लाइसेंस शुल्क पर तथा और दो माह सामान्य लाइसेंस शुल्क की दो गुनी राशि पर'' शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

''आगे दो माह सामान्य लाइसेंस शुल्क की चार गुनी राशि पर और उसके उपरांत दो माह संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समुचित प्रमाणन के अध्यधीन चिकित्सीय/शैक्षिक आधारों सहित विशेष कारणों पर सामान्य लाइसेंस शुल्क की छह गुनी राशि पर''

[सं.एफ.-1/18/98 ए.एन.]]

जे.पी. रत्नेश अपर सचिव

टिप्पण:—सा.का.नि. 576 के अंतर्गत लोक सभा सिचवालय की दिनांक 1-5-1974 की अधिसूचना संख्या एफ.1/18/74-ए.एन. II में प्रकाशित मूल नियम तथा तदनन्तर संशोधन इस प्रकार है:—

(एक) सा.का.ति. 279 (अ), दिनांक 17-6-1977

(दो) सा.का.नि. 566 (अ), दिनांक 1-12 -1978

(तीम) सा.का.नि. 439 (अ), दिनांक 7- 7-1979

(चार) सा.का.नि. 1110 (अ), दिनांक 26- 9-1986

(पांच) सा.का.नि. 1011 (अ), दिनांक 22-12 -1987

(छ:) सा.का.मि. 3 (अ), दिनांक 1- 1-1997

(सात) सा.का.नि. 67 (अ), दिनांक 6- 2-1997

(आठ) सा.का.नि. 142 (अ), दिनांक 20-3 -1998

व्याख्यात्मक ज्ञापन

लोक सभा सचिवालय (आवासों का आवंटन) नियम, 1974 के नियम 8 के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत्त/सेवान्त अवकाश के मामले में लाइसेंस शुल्क का सामान्य दर से भुगतान करने पर सरकारी आवास अपनें अधिकार में रखने की अनुन्नेय अवधि दो महीने है और लाइसेंस शुल्क की सामान्य राशि से दो गुनी राशि का भुगतान करने पर यह अवधि दो महीने के लिए और बढ़ाई जाती है। ये उवबन्ध 1-3-1997 लागू हैं।

भारत सरकार ने सरकारी आवासों का आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 के सा.नि. 317-बी-11 (2) में इस आशय के संशोधन किए हैं कि सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारी जिन्हें सरकारी आवास आबंटित हैं, सामान्य लाइसेंस शुल्क से चार गुनी राशि का भुगतान करके और दो महिने के लिए सरकारी आवास अपने अधिकार में रखने के पात्र होंगे तथा दतनन्तर सामान्य लाइसेंस शुल्क से छह गुनी राशि देकर चिकित्सीय/शैक्षिक आधारों पर यह आवास और दो माह अपने अधिकार में रख सकेंगे, बशर्तें कि इस संबंध में और सरकारी आवास रखने की उपर्युक्त अविध के लिए बढी हुई लाइसेंस शुल्क की राशि के भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट सहित दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो। इन संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से, 1 जनवरी, 1997 से लागू किया गया है।

भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों को भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित करने की दृष्टि में रखकर लोक सभा सचिवालय (आवासों का आवंटन) नियम में संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 जनवरी, 1997 से किया जा रहा है।

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 1998

G.S.R. 247(E).— In exercise of the Powers conferred by rule 45 of Fundamental Rules as made applicable to the officers of the Lok Sabha Secretariat by Recruitment and Conditions of Service Order number 185, dated the 19th December, 1957, the Speaker of the Lok Sabha hereby makes the following rules further to amend the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules, 1974, namely:—

- (1) These rules may be called the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) amendment Rules, 1998.
- (2) They shall be deemed to have come into force on 1st January, 1997.
- 2. In Lok Sabha Secretariat (allotment of Residences) Rules, 1974,

in rule 8, in the table below sub-rule 2, against item (ii) relating to retirement or terminal leave, after the words "two months on normal licence fee and another two months on double the normal licence fee occurring under the column relating to permissible period for retention of the residence, the following shall be added namely:—

"further two months on payment of four times the normal licence fee and subsequent two months on payment of six times the normal licence fee for special reasons involving medical/educational grounds subject to appropriate certification by the authorities concerned".

[No. F.1/18/98/AN-II]

J. P. RATNESH, Addl. Secy.

NOTE:—Principle rules published under the Lok Sabha Secretariat. Notification No. F.1/18/74-AN-II, G.S.R. 576 dated 1-5-1974 and subsequent amendments are as under:—

- (i) G.S.R. 279 (E), dated 17-6-1977
- (ii) G.S.R. 566 (E), dated 1-12 -1978
- (iii) G.S.R. 439 (E), dated 7-7-1979
- (iv) G.S.R. 1110 (E), dated 26-9 -1986

(v) G.S.R. 1011 (E), dated 22-12 -1987

(vi) G.S.R. 3 (E), dated 1-1 -1997

(vii) G.S.R. 67 (E), dated 6-2 -1997

(viii) G.S.R. 142 (E), dated 20 -3 -1998

EXPLANATORY MEMORANDUM

As per the provisions of the Rule 8 of Lok sabha Secretariat (allotment of Residences) rules, 1974, the permissible period of retention of government accommodation in the case or retirement/terminal leave is two months on payment of normal rate of licence fee and further two months on payment of double the normal licence fee. These provisions are in force with effect from 1-3-1997.

The Government of India have since made amendments in SR-317-B-11(2) of Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) rules 1963 to the effect that the retiring government servants who are allottee of government accommodation shall be eligible to retain the government accommodation for a further period of 2 months on payment of 4 times of the normal licence fee and subsequent 2 months on payments of 6 times of the normal licence fee on medical/educational grounds, subject to production of documentary proof in this regard, alongwith Bank draft towards payment of enhanced licence fee for the period of said retention. These amendments have been given retrospective effect from the 1st January, 1997.

In view of the retrospective implementation of the above instructions by the Government of India, the amendment in Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules are being given effect retrospectively with effect from 1st January, 1997.